निगम द्वारा यथा-निर्दिष्ट ए और ए आई वर्ग ।

7. ऐसे उद्योग जिनका उल्लेख मास्टर प्लान–1990 में वर्ग एच के रूप में आपत्तिजनक, खतरनाक और प्रदूषणकारी उद्योगों के रूप में किया गया है, उन्हें तदर्थ पंजीकरण योजना, 1994 में शामिल नहीं किया गया है ।

(ग) जैसे ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार का निर्णय प्राप्त हुआ था, दिल्ली नगर निगम ने इस मामले में तत्काल कार्यवाही की ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) दिल्ली नगर निगम के अनुसार जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है फैक्ट्री लाइसेंसिंग विभाग ने लाइसेंसिंग कार्यविधि को सरल बना दिया है ।

जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है नई औद्योगिक नीति के अधीन अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन आने वाले उद्योगों की सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाती है । अधिकतर मदों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है । अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन अब केवल 16 उद्योगों की एक संक्षिप्त सूची है । 836 मदें केवल लघु उद्योग द्वारा निर्माण के लिए आरक्षित हैं । उद्योगों के पंजीकरण की योजनाओं अर्थात लाइसेंस मुक्त उद्योग पंजीकरण योजना, छूट प्राप्त उद्योग पंजीकरण योजना और लोहे तथा इस्पात के लिए वस्त्र आयुक्त और विकास आयुक्त के पास पंजीकरण को समाप्त कर दिया गया । अन्य सभी उद्योगों को, जिनके लिए नई औद्योगिक नीति के अधीन लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है, एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है ।

उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग स्थापित किये जाना

7014. मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में बड़े भारी उद्योग स्थापित करने के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991 से 1993 के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी हेतु 398 आवेदन (मिश्रित आवेदन छोड़कर) प्राप्त हुए थे ।

1–4–94 की स्थिति के अनुसार इनके लिए 106 आशय पत्र दिए गए, 59 आवेदन नामंजूर किये गए और 103 आवेदनों के मामले में कोई औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक नहीं था । मामले वापस ले लिये गये थे ।

Demand of Indian Industry for level Playing field

7015. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Minister of Commerce has recently justified the demand of the Indian industry for a "level playing field' as per the news-item in the Hindustan Times, dated 19th April, 1994, under the caption the 'Commerce Minister Justifies demand for level-plying field;

(b) if so, the facts in this regard; and

(c) what action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b)

In reply to a question asked at a meeting organised by the Confederation of Indian Industry on 18th April, 1994, the Commerce Minister had said that India will not allow a situation where Indian Industry is wiped out. He had also stated that there must be a level playing field.

(c) Under the current economic reforms programme various measures have already been taken to enable the domestic industries attain international competitiveness.

Establishment of Investment Promotion office

7016. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the U.N.I.D.O. has recently suggested the establishment of an Investment Promotion office;

(b) if so, the deails thereof; and

(c) what action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The details in this regard are not available with Government.

Setting up of new factories

7017. SHRI O.P. KOHLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether permission is required to set up new factories in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the National Council for Applied Economic Research (NCAER) had carried out any survey in regard to the above; and

(d) if so, the findings and recommendations thereof and the action taken by Government thereon to remove the hurdles in the way of grant of permission to establish factories in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) under the New Industrial Policy, 16 industries under compulsory licencing and 6 idustries reserved for public sector require prior approval of the Government. In addition, medium/large scale units for manufacturing items reserved for small scale industries or seeking locational rtlaxation will have to obtain a licence.

(c) The National Council for Applied Economic Research (NCAER) has conducted 'Business Expectation Survey' (Round 9) in January, 1994.

(d) The findings of this Survey, inter-alia, are that:

(i) The industry is optimistic about the performance of the economy;

(ii) Imports of raw materials have decreased;

(iii) Exports are expected to rise; and

(iv) The regulatory framework varies across regions.

The Central Government is interacting with the State Governments on a continuous basis to ensure that Industrial Projects are implemented expeditiously.

Hindustan Photo Films

7018. SHRI SANJAY DALMIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state

(a) whether it is a fact that Hindustan Photo Films at Ootacamund in Tamil Nadu is in the red;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) what steps Government are taking to meet the targetted production during the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) Hindustan Photo Films (HPF) has incurred provisional losses of Rs. 117 crores and Rs. 70 crores in 92-93 and 93-94